an>

Title: The Minister of State in the Ministry of Parliamentary Affairs made a statement regarding Government Business during the week commencing the 6th February 2016 and submissions made by Members.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI S.S. AHLUWALIA): Madam Speaker, I beg to lay a statement regarding Government Business during the week commencing the 6th February, 2017.

*With your permission, Madam, I rise to announce that Government Business during the week commencing Monday, the 06th of February, 2017 will consist of:-

1. Consideration of any items of Government Business carried over from today's order paper:- *[It contains (a) Withdrawal of the Payment of Wages (Amendment) Bill, 2016, (b) Introduction of the Payment of Wages (Amendment) Bill, 2017, (c) Introduction of the Specified Bank Notes (Cessation of Liabilities) Bill, 2017, (d) Discussion on the Motion of Thanks on the President's Address].*
2. General discussion on the Union Budget for 2017-18.
3. Consideration and passing of the following Bills:-
   (i) The Payment of Wages (Amendment) Bill, 2017
   (ii) The Specified Bank Notes (Cessation of Liabilities) Bill, 2017
4. Consideration and agreeing to the amendments made by Rajya Sabha in the Enemy Property (Amendment and Validation) Bill, 2016 as passed by Lok Sabha, after it is passed by Rajya Sabha.

HON. SPEAKER: Now, submissions by Members. Shri Kodikunnil Suresh.

SHRI KODIKUNNIL SURESH (MAVELIKKARA): Madam Speaker, the following matters be included in the next week's agenda.

With the southwest monsoon rainfall from June to September being deficient by 34 per cent and the northeast monsoon from October to December being deficient by 62 per cent, Kerala State is facing a prolonged season of drought. I would request the Government of India to take necessary steps.

Kerala's Kuttanad region is facing a sever drinking water shortage despite being a waterlogged stretch of about 110,000 hectares. Therefore, I would request the Government of India to take necessary steps.

HON. SPEAKER: Shri Sushil Kumar Singh – Not present.

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल) : अध्यक्ष महोदया, कृपया निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में शामिल किया जाए--

(1) बिहार में दलित, मुसलमान एवं अति पिछड़े वर्ग के लोगों के बच्चों के शैक्षणिक विकास एवं कल्याण हेतु प्रत्येक जिले में दलित, मुसलमान एवं अति पिछड़ा छात्रावास खोला गया था, जिसकी स्थिति काफी जर्जर है एवं यह छात्रावास रहने के लायक नहीं है। ऐसी परिस्थिति में इन छात्रावासों की मरम्मती के साथ-साथ प्रत्येक प्रखंड में पांच-पांच दलित, मुस्लिम एवं अति पिछड़ा छात्रावास का निर्माण करने हेतु सख्त नियम बनाया जाए।

(2) भोजन, पेय पदार्थ, दवाइयों और अन्य उपभोक्ता पदार्थों की पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक के उपयोग की सुविधा अब इंसान के अस्तित्व के लिए खतरा बन गई है। नॉन बायो-डीग्रेडेबल प्लास्टिक से संगृहित सामग्री मिट्टी और पानी में हानिकारक रसायनों और भारी धातुओं का रिसाव करता है, जो कैंसर, जन्म दोÂा, टाइप 2 मधुमेह, श्वसन और हृदय की बीमारियों का कारण बनता है, जो कि स्वास्थ्य के साथ-साथ पर्यावरण के लिए भी गंभीर खतरा है। अत: प्लास्टिक उत्पादों की पूर्ण बंदी हेतु सख्त नियम बनाया जाए।

श्री ओम बिरला (कोटा) : अध्यक्ष महोदया, हमारी सरकार ने किसानों की समस्याओं के निवारण के लिए कई प्रयास किए हैं, परन्तु उनकी लम्बे अरसे तक की गई उपेक्षा की वजह से अभी भी वे बदहाली में हैं। किसानों के सामने कृषि की बढ़ती लागत के कारण आर्थिक संकट उत्पन्न होना शुरू हो गया है। इस स्थिति को ठीक करने हेतु वैसे किसान, जिनके पास 2 एकड़ या उससे भी कम जमीन है, उनका बिजली शुल्क पूरी तरह माफ कर दिया जाए। साथ ही साथ ऐसे किसानों को मुफ्त में बीज भी उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है।

सहकारिता आन्दोलन का ध्येय किसानों, लघु व्यावसायियों, जनसाधारण को बिचौलियों के

शोÂषण से मुक्त कराते हुए उनकी पारस्परिक सहयोग पर आधारित सामूहिक आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहित करना है। इनको और सशक्त करने के लिए ग्राम सहकारी बैंकों को बैंकिंग लाइसेंस दिए जाने की आवश्यकता है।

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Madam Speaker, the following two items may be included in the List of Business in the week commencing from 6th February, 2017.

1. Crisis in cashew industry due to the imposition of import duty on raw cashew nuts.
2. Functioning of self financing institutions in India and its impact on quality education.

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : अध्यक्ष महोदया, अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित लोक महत्व के विÂषयों को शामिल कर सदन में चर्चा कराने की कृपा करें--

(1) मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत चित्रकूट धाम कर्वी से कानपुर तक चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रैस को लखनऊ तक बढ़ाने की मांग स्थानीय लोग काफी दिन से कर रहे हैं। अत: उसे लखनऊ तक बढ़ाने व उसमें एक एसी चेयरकार लगाने हेतु सदन में चर्चा कराकर समुचित निर्देश दिया जाए।

(2) मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत बांदा जनपद में केन्द्रीय विद्यालय इसी सत्र से कृÂिष महाविद्यालय बांदा में प्रस्तावित स्थल पर शुरू किया जाए एवं चित्रकूट जनपद में अधिगृहित जमीन पर वहां केन्द्रीय विद्यालय भवन निर्माण हेतु शीघ्र चर्चा कराकर समुचित निर्देश दिए जाएं।

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) : अध्यक्ष महोदया, कृपया निम्नलिखित विषय आगामी सप्ताह की कार्य सूची में संलग्न करने का कष्ट करें--

(1) मेरे लोक सभा क्षेत्र खीरी में जनजाति बाहुल्य क्षेत्र (गौरी फण्टा-चादन चौकी) ब्लॉक पलिया में स्थित है। पूर्व से स्वीकृत 17 कनेक्टिविटी टॉवर विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र न देने के कारण व ग्राम बनवीर पुर (ब्लॉक - पलिया) में स्वीकृत टॉवर लगाने को कार्यदायी संस्थान को आदेश न देने के कारण लगाया व प्रारंभ नहीं किया जा सका है। बेहतर कनेक्टिविटी हेतु ये सभी टॉवर अति शीघ्र लगाए जाएं।

(2) मेरे लोक सभा के पलिया परिक्षेत्र में स्थित हवाई पट्टी, जिसका निर्माण लगभग 20 वर्ष पूर्व करोड़ों रुपये खर्च करके किया गया था तथा रख-रखाव पर अब भी बड़ी रकम खर्च की जा रही है। अत: उक्त हवाई पट्टी को व्यावसायिक उड़ानों हेतु खोला जाए तथा पलिया से लखनऊ प्रतिदिन व दिल्ली हेतु सप्ताह में दो उड़ानें प्रारंभ की जाए।

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं अनुरोध करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र के लोक महत्व के विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए।

(एक) बिहार में दलित, आदिवासी, मुस्लिम वर्ग के छात्रों की पढ़ाई के लिए मिलने वाली पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति को सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया है। वÂर्ष 2015-16 व उसके पूर्व के वर्षों में नामांकन कराए दलित छात्रों की छात्रवृति को जहां सरकार ने डेढ़ लाख से घटाकर अधिकतम 15 हजार रुपये कर दिया है, वहीं वर्तमान वित्त वर्ष 2016-17 से दलित आदिवासियों की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति को ही बंद कर दिया है। चालू वित्त वष्Â◌ान से दलित छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृति को बंद कर सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के जरिए इंटर उत्तीर्ण छात्रों को चार लाख रुपये तक कर्ज दिलाने की बात कर रही है। 11वीं व 12वीं की पढ़ाई कर रहे दलित छात्र जो इंटर उत्तीर्ण नहीं है, जिसके चलते उन्हें कर्ज नहीं मिलेगा और न ही उन्हें पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति मिलेगी, ऐसे में उनकी पढ़ाई कैसे पूरी होगी? चालू वित्त वर्ष के 10 माह बाद भी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति के लिए न तो दलित छात्रों से आवेदन लिए गए हैं और न ही कोई प्रक्रिया शुरू की गई है।

अतः दलित आदिवासी छात्रों को मिलने वाली छात्रवृति को पूर्व की भांति चालू करने के लिए सख्त नियम बनाया जाए।

(दो) देश में फैली बेनामी संपति का उपयोग रियल एस्टेट, गहने, बनाव या अन्य चल या अचल संपति के रूप में होता है, इसकी निÂपक्ष जांच कराकर जांच में पाई गई बेनामी संपति को जब्त करते हुए भविष्य में पैदा होने वाली बेनामी संपति को रोकने के लिए प्रत्येक लेन-देन को पारदर्शी बनाया जाए एवं देशभर में राजनीतिक दलों को मिलने वाले किसी भी तरह के चंदे को डिजीटल माध्यम से भुगतान करने तथा राजनीतिक दलों को चंदा लेने के बजाए सरकार के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु सख्त विधि नियम बनाया जाए।

श्री विद्युत वरन महतो (जमशेदपुर): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं अनुरोध करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र के लोक महत्व के विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए।

(एक) मेरे संसदीय क्षेत्र जमशेदपुर के अंतर्गत घाटशिला या मुसाबनी में सैनिक स्कूल खोला जाए। साथ ही साथ द्वितीय विश्व युद्ध एवं बांग्लादेश की लड़ाई के समय सैनिकों के साथ धालभूमगढ़ और चाकुलिया सैनिक एयरपोर्ट को इस्तेमाल किया गया था इस एयरपोर्ट को विकसित किया जाए, क्योंकि यह औद्योगिक क्षेत्र के साथ साथ पूरा इलाका माइंस से भरा पड़ा है। इससे न सिर्फ झारखंड, बल्कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के लोगों को फायदा होगा। ये सीमावर्ती क्षेत्र है।

(दो) मेरे संसदीय क्षेत्र जमशेदपुर के बोड़ाम, पटमदा, कांटिन (पश्चिम बंगाल) तथा बहरागोड़ा, घोड़ाबांधा, पोटका (उड़ीसा) का सीमावर्ती क्षेत्र पड़ता है यहां के लोगों का टावर पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा का सिग्नल पकड़ता है, जिसके कारण रोमिंग चार्ज ज्यादा कटता है। यहां के आदिवासी बाहुल्य, गरीब, उग्रवाद प्रभावित, पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण लोगों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, रोमिंग कटने के कारण यहां के लोग मोबाइल से बात नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण परेशानियों का सामना करना पड़ता इसलिए नए टावर लगाए जाएं।

SHRI K. ASHOK KUMAR (KRISHNAGIRI): Hon. Speaker Madam, the following item may be taken for discussion during the next week's business.

In my constituency, Kelamangalam railway station is used by people of 10 villages. 12 goods trains and 6 express trains pass through this station and 3 passenger trains are stopped here. At this station, the platform height is very low. It is not fit for use by elderly people, ladies and passengers. The 500 metre platform's height should be increased accordingly.